सुन्दरता/ विष्णु खरे

एक सुन्दर चिड़िया
न बहुत छोटी न बड़ी
आम की डाल पर बैठी हुई
जिसे देखते रहने का दिल हो

न बहुत सुन्दर तितली
न बहुत छोटी न बड़ी
शाख़ की बौरों पर मँडलाती बैठती उड़ती
जिसे हथेली पर बैठाने का दिल हो

क्या चिड़िया में इतना सम्मोहन था
या अपने गहरे रंगों से
बौरों और डालियों में वह इतनी यकसार हो गई थी
कि तितली उसे देख न सकी
जबकि चिड़िया उसके चटख रंगो
और मंडलाने को शायद एकटक
देख रही होगी

चिड़िया और तितली अब ऐसे
दीख रहे थे
जैसे परस्पर एक असंभव चुम्बन में
दोनो परस्पर मुख छोड़ना न
चाहते हों
तितली के पंख वस्त्रों की तरह फिसल नीचे
पत्तियों के तल तक तिरते गए
उसका थरथराता शरीर चिड़िया की
जीभ से आत्मसात हुआ

तृप्ति के बाद चिड़िया संयत हुई
फिर उसने जो गाया वह
उसकी सुन्दरता जैसा ही सुन्दर था
उसमें पराग और मधुर मधु थे
उस काल

सांझ हो रही थी
डूबते सूरज को वह कब तक
बैठी देखती
उसे लौटना था अपने वृक्ष पर
अपने नीड़ को
जहां किसे पता कौन -कौन
उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा

लौट पाती यदि शाम को तो वह
तितली कहां लौटती ?
क्या वहां उसकी बाट जोही गई होगी ?
दूसरी तितलियों का यह
सोचने-कहने का ढंग कैसा होगा कि
वह नहीं आई अभी तक ?

नीचे अपनी बाँबी में ले जाती हुई
लाल चींटियों से छुड़ाकर
एक बच्ची ने अलबत्ता
सहेज कर रखे अपनी किताब में
दो वह सुन्दर पंख जब तक वह बचे।

(वरिष्ठ हिन्दी कवि विष्णु खरे का हॉल में निधन हुआ। हार्दिक श्रद्धांजलि)

खबर (दार) झरोखा — **वीना**

पूंजीपतियों की संपत्ति में इजाफे का खेल है एनपीए

कहा जा रहा है कि दिन पर दिन देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ रुपया अंबानी-अडानी, माल्या, चोकसी, मोदी आदि की तिजोरियों में जाकर नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट यानी एनपीए बनता जा रहा है। मेरा मानना है कि रुपये को एनपीए कहना धन-रुपये का अपमान है, उस पर कलंक है। सच्चाई ये है कि धन कभी भी नॉन परफॉर्मिंग नहीं हो सकता। अगर ओलम्पिक में धन को दौड़ाया जाए, तो सारे धावक मैडल भारत के धन की ही झोली में गिरेंगे। इतनी तेज रफतार से दौड़ता है हमारा रुपया!

देश के बैंको से निकल कर कब स्विस और पनामा आदि-आदि हजारों मील दूर विदेशी बैंकों की तिजोरियों में आराम करने पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता। मेहुल चोकसी एंटिगुआ के स्वर्ग में विचर रहे हैं। विजय माल्या इंग्लैंड में मज़े लूट रहे हैं। नीरव मोदी शायद अभी तय नहीं कर पाए कि कौन सा देश बेहतर है चुराए धन पर पसर कर विश्राम करने के लिए। ये तो रहा विदेशों में प्रदर्शन। अब देश में रुपये का कमाल देखिये-कब लोगों की जेबों, बैंक एकाउंटों से दौड़-दौड़कर करोड़ों रुपया दिल्ली में बीजेपी के मल्टी स्टार मुख्यायल में जड़ गया किसी को भनक भी नहीं लगी। पानी पर हेलिकॉप्टर दौड़ाने का मजा। चुनावों में प्राइवेट जेट सभा। 600 सौ करोड़ का रफाल सौदा 1600 सौ करोड़ में आदि-आदि और नासमझ लोग हैं कि फिर भी रुपये-पैसे पर एनपीए की तोहमत लगाए जाते हैं!

अब लोग कहेंगे कि पैसा अगर इतना ही मेहनती है तो जितनी तेजी से नेताओं-अफसरानों, उद्योगपतियों के ठाट-बाट में लग जाता है देश के टैक्स देने वाले नागरिक-वोटर की सेवा वैसी मुस्तैदी से क्यों नहीं करता? क्यों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? क्यों मेहनतकश-मजदूर भूखा-नंगा फुटपाथों पर पड़ा सड़ता है? जिनके जहन में ऐसे बेकार ख्याल आते हैं क्या वो नहीं जानते कि -

''पैसा पैसे को खींचता है।'' ये सिर्फ एक कहावत नहीं सच्चाई है। अंबानी-अडानी, मोदी, चोकसी, टाटा-बिड़ला आदि-आदि पहले पार्टियों के चुनाव प्रचार में नोटों की गड्डियों पे गड्डियां फेंकते हैं। जीत-हार की रेस लगाने वाली पार्टियों के कुर्ते-सूटों के पीछे इन गड्डियों के मालिकों से किए गए कसमें-वादों की चिप चिपकी रहती है। जो भी सरकार में पहुंचे उसे आम लोगों के खजाने तक इस चिप को पहुंचाना होता है। सरकार और उसके कारिंदे जिधर, जिस सरकारी महकमें-खज़ाने में जाते हैं ये चिप वहां रखी गड्डियों को खींचकर अपने मालिक तक पहुंचा देती हैं।

तो पहले पैसा इनवेस्ट करना पड़ता है। किसान-मजदूर सोचते हैं कि उनका खून-पसीना, महीनों-सालों की मेहनत से सींची फसल पैसा खींच लाएगी! ऐसा सोचना-मानना उनका बचपना नहीं है तो और क्या है? गलती आपकी है कि इतनी छोटी सी बात आपको समझ नहीं आती मजदूरों-किसानों कि पैसा पैसे को खींचता है। इसके लिए चिल्ला-चिल्लाकर सरकारों को दोष क्यों देते हो?

जो पैसे से पैसा बनाना जानता है उसी को जीने का और शान से जीने का हक हासिल है। अभी तक यही दस्तूर है दुनिया में। मजदूर-किसानों, आदिवासियों में अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि पैसे को खींचने के लिए पैसा कहां से जुटाया जाए तो जिन्दा तो वो रह नहीं पाएंगे। खुशहाल जीवन की तो कल्पना ही नाजायज मांग है।

अब क्योंकि जी नहीं सकते तो जाहिर है मरना पड़ेगा। यहां पर बीजेपी सरकार गरीब वोटरों के वोट का एहसान चुकाने के लिए एक मौका मुहैया करवा रही है। हाय पेट्रोल महंगा कर दिया...हाय गैस की कीमते बटुए में छेद कर रही हैं...हाय भूखे मर गए..भी न मिला...आदि-आदि रोना रोकर कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि राष्ट्रवादी, देशभक्त बनकर, एक-दूसरे का गला, हाथ-पैर काट-पीसकर शहीदों की गौरवपूर्ण मौत मरो। ऐसी मृत्यु की इच्छा रखने वालों को सरकार शहीद का तमगा देगी।

अगर कोई सरकार की इस स्कीम को अपनाता है तो उसे ऐसी कुछ डिमांड रखने का अधिकार भी मिल सकता है जिसे सरकार खुशी-खुशी मान ले। मसलन जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को मरवाकर उनका नाम इंडिया गेट पर खुदवा दिया। ऐसा कोई गेट-वेट बनवाने की मांग पर गौर किया जा सकता है। रोजगार-रोटी की हाय-तौबा छोड़ने पर इतना हक तो बनता है।

इस स्कीम को चुनने वालों के लिए सरकार एक और सुविधा दे रही है। जो वोटर अब मोदी-शाह, योगी, सिंघल, कटियार, भागवत, आडवानी-अटल आदि के जान दांव पर लगाऊ, भाषणों से बोर हो चुके हैं, जान गंवाने से परहेज करने लगे हैं। या मजा नहीं आ रहा जान देने में अब और मजबूरन रोजगार-व्यापार की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान-हिंदुस्तान में शांति बहाली की तरफ जिनका ध्यान भटकने लगा है।

ऐसे भूखे-प्यासे-नंगे कुत्ते की मौत मरने वालों को फिर से पूरे जोशो-खरोश से सिर उठाकर कत्ल होने के लिए तैयार करने का हुनर रखने वाला पाकिस्तानी मूल का, हिंदू धर्म का मुरीद, मुसलमान जमूरा कनाडा से आयात किया गया है।

ये जमूरा आजकल गली-गली यलगार कर रहा है कि रोटी-रोटी मांगकर हिंदू जात को शर्मिंदा करने से अच्छा है की पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो। जो हिंदुस्तानी मुसलमान उसकी तरह मुसलमान होते हुए भी दिल से हिंदू नहीं है, वंदे मातरम न बोले, उसका नामोनिशान मिटा दो। जब तुम ऐसा प्रण ले लोगे तो भूख-प्यास का एहसास खतम हो जाएगा। कायर हिंदू और एहसान फरामोश मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। और इन्हें जहन्नुम पहुंचाकर जो चंद बहादुर जन्नत के हकदार बच जाएंगे उन्हें मनुस्मृति के अनुसार वर्ण कतार में लगाकर उनका लोक-परलोक सफल बनाया जाएगा।

जो लोग कनाडियन जमूरे के इस उपदेश से इत्तेफाक नहीं रखते और गरीबी-गुरबत से परेशान हैं। और जिन्होंने नोटबंदी का मजे ले-लेकर इसलिए समर्थन किया था कि उन्हें लूटने वाले, काला धन जमा करने वालों पर गाज गिरेगी। वो भी लाईनों में खड़े होंगे और उनकी काली कमाई मोदी साहेब उनमें बांट देंगें पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके लिए मेरी राय है कि मोदी की धोखेबाजी की सजा इस जमूरे को न दें। इस पर विश्वास करें। सभी गरीब-गुरबे हिंदू-मुसलमान, सवर्ण-दलित-पिछड़े,आदिवासी एक-दूसरे को मारकाट कर खत्म कर लें।

ऐसा क्यों करें? इसलिए कि अंबानी-अडानी, टाटा-बिड़ला आदि-आदि जिनकी एक सेकेंड-मिनट-दिन की कमाई लाखों-करोंड़ों-अरबों में बताई जाती है और जो बड़ी शान से सस्ते नौकरों की बदौलत, किसान-मजदूर के दम पर अपने आलीशान कमरों में बैठ पैसा बटोरने वाली लूट की योजनाएं बनाते हैं। जब कोई जी-हजूरी के लिए बचेगा ही नहीं तो इन्हें अपने घर का झाड़ू-पोछा, संडास तक खुद साफ करना पड़ेगा। खाने के लिए अनाज चाहिये तो खुद खेत में पसीना बहाना पड़ेगा।

चिनाई-पुताई-प्लमबरिंग, एक-एक काम खुद करना होगा। और आखिरकार ये भी आप लोगों की तरह मजदूर-किसान बनने में अपना सारा वक्त जाया करेंगे। पढ़ने-लिखने, सोचने, डकैती की योजनाएं बनाने का वक्त ही नहीं बचेगा। ऐसे में इनका वक्त भी आपके वक्त की तरह कोडियों का हो जाएगा। क्योंकि पैसा जो इनके घरों-बैंकों में ठुसा पड़ा है वो पैसे को ही तो खींच सकता है। उन मजदूर-किसानों को बेगारी के लिए जिंदा नहीं कर सकता जिन्होंने कब्रों-चिताओं को अपनी हर जरूरत का सामान बना लिया हो।

अरबों रुपये लुटा कर जो संसद पहुंचा, वह देश लूटेगा ही

जिस संसद में 218 सांसद दागदार हैं, उसी संसद के एक पूर्व सदस्य से अरबों रुपये लेकर कर्नाटक की सियासत और देश की संसद अगर 2002 से लेकर 2016 तक चलती रही तो यह क्यों न मान लिया जाये कि संसद ऐसे ही चलती है।

पुण्य प्रसून वाजपेयी,
वरिष्ठ टीवी पत्रकार

एक मार्च 2016 को विजय माल्या संसद के सेन्ट्रल हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलते हैं। दो मार्च को रात ग्यारह बजे दर्जन भर बक्सों के साथ जेय एयरवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना हो जाते हैं। फ्लाइट के अधिकारी माल्या को विशेष यात्री के तौर पर सारी सुविधाये देते हैं और उसके बाद देश में शुरु होता है माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला या कहें कार्रवाई दिखाने का सिलसिला।

क्योंकि देश छोड़ने के बाद देश के 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ याचिका डालते हैं, जिसमें बैक से कर्ज लेकर अरबो रुपये न लौटाने का जिक्र होता है और सभी बैंक गुहार लगाते हैं कि माल्या देश छोड़कर ना भाग जाये इस दिशा में जरुरी कार्रवाई करें। माल्या के देश छोड़ने के बाद ईडी भी माल्या के देश छोडने के बाद अपने एयरलाइन्स के लिये लिये गये 900 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजने का केस दर्ज करता है।

माल्या के देश छोड़ने के बाद 13 मार्च को हैदराबाद हाईकोर्ट भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करता है, क्योंकि माल्या जीएमआर हेदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम जो पचास लाख का चेक देते हैं, वह बाउंस कर जाता है। 24 अप्रैल को राज्यसभा की ऐथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में माल्या को राज्यसभा की सदस्यतता रद्द करने की बात इस टिप्पणी के साथ कहती है कि 3 मई को वह माल्या को सदन से निलंबित किया जाये या नहीं, इस पर फैसला सुनायेगी।

फैसले के 24 घंटे पहले यानी 2 मई को राज्यसभा के चैयरमैन हामिद अंसारी के पास विजय माल्या का फैक्स आता है, जिसमें वह अपने उपर लगाये गये आरोपों को गलत ठहराते हुए राज्यसभा की सदस्यतता से इस्तीफा दे देते हैं। अगले दिन यानी तीन मई 2016 को राज्यसभा के एथिक्स कमेटी माल्या की सदस्यता रद्द करने का फैसला दे देती है। उसके बाद जांच एजेंसियां जागती हैं। पासपोर्ट अवैध करार दिये जाते हैं।

विदेश यात्रा पर रोक लग जाती है। तमाम संपत्ति जब्त करने का ऐलान हो जाता है और किसी आर्थिक अपराधी यानी देश को चूना लगाने वाले शख्स के खिलाफ कौन-कौन सी एजेंसी क्या क्या कर सकती है, वह सब होता है। चाहे सीबीआई हो आईबी हो ईडी हो या फिर खुद संसद ही क्यो न हो।

तो क्या वाकई देश ऐसे चलता है जैसा आज कांग्रेसी नेता पुनिया कह गये कि अगर संसद के सीसीटीवी को खंगाला जाये तो देश खुद ही देख लेगा कि कैसे माल्या और जेटली एक मार्च 2016 को संसद के सेन्ट्रल हाल में बात नहीं, बल्कि अकेले गुफ्तगू भर नहीं बल्कि बैठक कर रहे थे। यह झूठ हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, माल्या मिले थे, पर बतौर राज्यसभा सांसद वह तब किसी से भी मिल सकते थे। पर कोई बैठक नहीं हुई। तो सवाल तीन हैं। पहला, जो संसद कानून बनाती है उसे ही नहीं पता कानून तोड़ने वाले अगर उसके साथ बैठे हैं तो उसे क्या करना चाहिये।

दूसरा, सांसद बन कर अपराध होता है या अपराधी होते हुये सांसद बनकर विशेषाधिकार पाकर सुविधा मिल जाती है। तीसरा, देश में कानून का राज के दायरे में सांसद या संसद नहीं आती है क्योंकि कानून वही बनते हैं। दरअसल तीनों सवालो के जवाब उस हकीकत में छिपे हैं कि आखिर कैसे विजयमाल्या सांसद बनते हैं और कैसे देश की संसदीय राजनीति करोडो के वारे न्यारे तले बिक जाती है।

उसके लिये विचार, कानून या ईमानदारी कोई मायने नहीं रखती है। कैसे? इसके लिये आपको 2002 और 2010 में राज्यसभा के लिये चुने गये विजय माल्या के पैसो के आगे रेंगते कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के जरीये समझना होगा। या फिर कार्नाटक में मौजूदा सत्ताधारी जेडीएस का खेल ही कि कैसे करोड़ों-अरबों के खेल तले होता रहा इसे भी समझना होगा और संसद पहुंचकर कोई बिजनेसमैन कैसे अपना धंधा चमका लेता है इसे भी जानना होगा।

2002 में कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता थी तो राज्यसभा के चार सदस्यों के लिये चुनाव होता है। चुने जाने के लिये हर उम्मीदवार को औसत वोट 43.8 चाहिये थे। कांग्रेस के तीन उम्मीदवार जीतते हैं और 40 विधायकों को संभाले बीजेपी के एक मात्र डीके तारादेवी सिद्दार्थ हार जाते हैं। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिये कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार विजय माल्या को जीता देती है।

और मजे की बाज तो ये भी होती है कि बीजेपी के चार विधायक भी तब बिक जाते हैं। यानी रिजल्ट आने पर पता चलता है कि विजय माल्या को 46 वोट मिल गये। यानी दो वोट ज्यादा और तब अखबारों में सुर्खियां यही बनती है कि करोड़ों का खेल कर विजय माल्या संसद पहुंच गये। तब हर विधायक के हिस्से में कितना आया इसकी कोई तय रकम तो सामने नहीं आती है, लेकिन 25 करोड रुपये हर विधायक के आसरे कर्नाटक के अखबार विश्लेषण जरूर करते हैं।

आप सोच सकते हैं कि 2002 में 46 वोट पाने के लिये 25 करोड़ के हिसाब से 11 अरब 50 करोड रुपये जो बांटे गये होंगे, वह कहां से आये होंगे और फिर उसकी वसूली संसद पहुंच कर कैसे विजय माल्या ने की होगी। क्योंकि वाजपेयी सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनती है और उड्डयन मंत्रालय एनसीपी के पास जाता है।

प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री बनते हैं और तब विजय माल्या उड्डयन मंत्रालय की समिति के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। और अपने ही धंधे के ऊपर संसदीय समिति का हर निर्णय कैसे मुहर लगाता होगा, ये बताने की जरुर नहीं है। उस दौर में किगंफिशर की उड़ान कैसे आसामान से उपर होती है, ये कोई कहां भूला होगा। पर बात यही नहीं रुकती। 2010 में फिर से कर्नाटक से 4 राज्यसभा सीट खाली होती हैं।

इस बार सत्ता में बीजेपी के सरकार कर्नाटक में होती है। और औसत 45 विधायकों के वोट की जरुरत चुने जाने के लिये होती है। बीजेपी के दो और कांग्रेस का एक उम्मीदवार तो पहले चरण के वोट में ही जीत जाता है, पर चौथे उम्मीदवार के तौर पर इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार फंस जाता है। क्योंकि कांग्रेस के पास 29 वोट होते हैं।

बीजेपी के पास 26 वोट होते हैं और 27 वोट जेडीएस के होते हैं। जेडीएस सीधे करोड़ों का सौदा एकमुश्त करती है। 5 निर्दलीय विधायक भी माल्या के लिये बिक जाते हैं और 13 वोट बीजेपी की तरफ से पड़ जाते हैं। यानी 2002 की सुई कांग्रेस से घूमकर 2010 में बीजेपी के पक्ष में माल्या के लिये घूम जाती है।फिर कर्नाटक के अखबारों में खबर छपती है करोड़ों-अरबों का खेल हुआ है।

इस बार रकम 25 करोड़ से ज्यादा बतायी जाती है। यानी 2002 की साढ़े ग्यारह अरब की रकम 20 अरब तक बतायी जाती है। फिर ये रकम कहां से विजय माल्या लाये होंगे और जहां से लाये होंगे, वहां वापस रकम कैसे भरेंगे। ये खेल संसद में रहते हुये कोई खुले तौर पर खेलता है।

इस दौर में आफशोर इन्वेस्टमेंट को लेकर जब पनामा पेपर और पैराडाइड पेपर आते हैं तो उसमें भी विजय माल्या का नाम होता है। यानी एक लंबी फेरहिस्त है माल्या को लेकर। लेकिन देश जब नये सवाल में जा उलझा है कि संसद में 1 मार्च 2016 को विजय माल्या लंदन भागने से पहले वित्त मंत्री से मिले या नहीं? या क्या वह वाकई कह रहे थे कि वह भाग रहे हैं, पीछे सब देख लेना। पीछे देखने का सिललिसा कैसे होता है, ये पूरा देश देख समझ सकता है।

लेकिन आखिरी सवाल तो यही है कि जिस संसद में 218 सांसद दागदार हैं, उसी संसद के एक पूर्व सदस्य से अरबों रुपये लेकर कर्नाटक की सियासत और देश की संसद अगर 2002 से लेकर 2016 तक चलती रही तो यह क्यों न मान लिया जाये कि संसद ऐसे ही चलती है और अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचेगा वह देश को नहीं तो किसे लूटेगा।